Health Ministry are given in the note that has been supplied to the hon. Members.

Shri Krishnacharya Joshi : May I know the names of the States which have undertaken this scheme?

Shrimati Chandrasekhar: There are 12 States in India which have undertaken comprehensive maternity and child welfare schemes for the promotion of health and welfare of children. They are: Delhi, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Travancore-Cochin, Hyderabad, Assam, Andhra, Mysore Bombay, West Bengal and Saurashtra. The last four States will be implementing the schemes shortly.

Shrimati Sushama Sen: May I know whether there is any liaison between the Health Ministry and the Central Social Welfare Board for promoting the welfare of children, and if so, what is the liaison?

Shrimati Chandrasekhar : I would require notice.

फसलों का कीड़ों से बचाव

*१६१७. श्री विभूती मिश्राः क्या वास्त्र और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों की जांच करवाई है:
- (स) यदि हां तो विभिन्न क्षेत्रों में कितने प्रकार के की हैं फसल को हानि पहुंचाते हैं ;
- (ग) उनसे प्रति वर्ष कितनी हानि होती है; ग्रीर
- (घ) ६न कीड़ों से फसलों का बचाव करने के लिये किन उपायों का पता लगाया गया है ?

हावि मंत्री (डा॰ पी॰ एस॰ देशमुख): (क) से (घ) सभा की टेविल पर एक विवरण रख दिया गया है। [देखिये परि-विषट १०, अनुबन्ध संख्या द्

भी विमूति विश्वः यह जो विवरण में इसमों को कीड़ों से बवाने के उपचार दिये गये हैं, क्या इनके प्रचार का गांवों में सरकार प्रज्ञन्घ कर रही है ?

डा॰ पी॰ एस॰ देशमुखः : इस विषय की जानकारी काश्तकारों को देने के खिये राज्य सरकारों ने काफी प्रयत्न किये हैं

श्री विभूति मिश्राः शान के लिये इस विवरण में दिया गया है:

"Dusting with 5 percent BHC; Spraying with 0.25 per cent DDT; Flooding the field and killing the larvae by dislodging them in kerosen ised water".

भगर ये सब दवाइयां एक एकड़ भूमि में उपयोग की जायं तो कितना खर्च पडेगा?

डा॰ पी॰ एस॰ देशमुख : इसका कुछ अन्वाजा नहीं है । अगर कहीं ये बीमारियां शुरू हों और उसी वक्त इनका इसाज कर लिया जाय तो उससे दुसरे कास्त-कारों को फायदा होता हैं। अगर एक एकड़ में कुछ ज्यादा पैसा भी लगा जाता है तो उससे जो फायदा होता है वह बहुत ज्यादा होता है वह बहुत ज्यादा होता है व

श्री विभूति मिश्रा: क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि यह जो की ज़ा लगता है इसके लिये कोई सस्ती भीर गांव वालों की समझ में भासानी से भाने वाली दवा निकालो जाय?

डा० पी० एस० बेंशमुक्त: ग्रगर कोई सस्ती दवा हो जिससे इलाज हो सकता हैं तो हम ग्रवश्य उस पर विचार करेंगे।

Passenger Amenities

*1918. Pandit D. N. Tiwary : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the remarks of the General Manager, North Bastern Railway, made on the 31st May, 1955 at Kurseong on the occasion of the meeting of the Passenger Amenities Sub-committee of the

North Eastern Railway Zonal Consultative Committee to the the work of providing amenities could not be ward at present;

Zonal Consultative effect that passengers pressed for-

- (b) if so, whether Government are in agreement with the views expressed by the General Manager; and
- (c) if not the steps taken to steep up the work of passengers amenities in the North Eastern Railway?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Railways and Transport (Shri Shahnawaz Khan): (a) The General Manager had stated that a large number of works carried forward from the previous year could not be pressed forward to the extent desired due to the pre-occupation of the Railway engineers with the restoration of the breached section.

- (b) Does not arise.
- (c) The works are being pressed forward to the maximum extent feasible.

पंडित ही एन तिवारी : मैंने पहले प्रश्न में भी इस विषय पर सप्लीमें-टरी प्रश्न किया था । मैं यह जानना बाहता था कि ग्रानरेबल मिनिस्टर के ग्रलावा क्या ग्रीर प्रिकारी भी वहां गये हैं ग्रीर उन्होंने देखा है कि वहां पर पैसिजर एमेनि टीज का स्तर कितना लो है ?

भी शासनवाज कां : हाथी के पैर में सब का पैर भ्राजाता है । मिनिस्टर साहब ने देख लिया तो सब ने देख लिया ।

पंडित डी॰ एन॰ तिबारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि एन॰ ई॰ रेलवे की पैंसिजर ऐमेनिटीज को भौर रेलवेज के बराबर लाने में कितने दिन भौर लगगे भौर उसके लिये क्या प्रयत्न हो रहा है?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (भी एल० वी० झास्त्री) : पालियामेंटरी सेकेटरी साहब ने जरा गलती की है। मेरा पैर हाथी का पैर तो हो ही नहीं सकता जहां तक सुविषां मों का सवाल है, नार्थ ईस्टर्न रेलवे, हमारे जमाने से नहीं, कम्पनी के जमानें से इस मामले में काफी पीछे रही है कम्पनी ने जाने से पहले प्रपना काम सराब कर दिया था ग्रौर उसको सुधारने में समब लगेगा। हम एन० ई० रेलवे को हपया देने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं,बल्कि ग्रौर रेलवेज से हम एन० ई० रेलवे को ज्यादा रुपया दे रहे हैं। ऐसी हालत में माननीय सदस्य को कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये। मगर उसको सुधारने में कुछ समय तो लगेगा, ग्रौर हम उधर की हालत को ठीक करने के लिये बहुत कोशिश कर रहे हैं।

पंडित डी॰ एन॰ तिवारी : कम्पनी के समय में एन॰ ई॰ रेलवे का पैसिजर माड़ा और लाइनों से कम था, इसलिये ग्रगर लोगों को कुछ तकलीफ होती थी तो उसको बरदाइत कर लेते थे । लेकिन ग्राज भाड़ा सब रेलों के बराबर है ग्रीर एमेनिटीज भीर लाइनों से बहुत नीचे हैं ऐसी हालत में क्या गवर्नमेंट भाड़े में कुछ कमी करने की बात सोच रही है ।

श्री एल बी शास्त्री: मेरे स्थाल में यह कहना कि कम्पनी के जमाने में भाड़ा बहुत कम था, ठीक नहीं है। मुझे इस रेलवे पर सफर करने का बहुत ज्यादा तजर्बा है। बनारस से इलाहाबाद के बीच किराये में सिर्फ डेड या दो ग्राने का फर्क था। वह अन्तर बहुत ज्यादा नहीं था। भ्रव अगर किराया डेढ़ भ्राना बढ़ गया है तो हमने कम्पनी के जमाने से बहुत ज्यादा सुविधायें भी दे दी हैं।

श्री विभूति मिश्र : पहले जब इस लाइन पर २ पाई प्रति मील किराया था तो दूसरी लाइनों पर ढाई पाई फी मील था । श्रव इस लाइन पर दूसरी लाइनों के बराबर किराया हो गया है । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उसी हिसाब से तीसरे, दूसरे श्रीर पहले दर्जे में इस लाइन पर एमेनिटीज भी बढ़ गयी हैं, ग्रगर एसा नहीं है तो क्या इनमें सुषार होने की ग्राशा की जा सकती है ? श्री एस॰ बी॰ शास्त्री: मैं देखंगा। लेकिन ग्रगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि हम कम्पनी का इन्तिजाम फिर से लावें तो वह हमारे लिये मुस्किन नहीं है।

Roads in Andamans

*1920. Shri Bhagwat Jha Azad : Will the Minister of Transport be pleased to state whether it is a fact, that Government propose to construct a trunk road linking the three main islands in the Andaman Islands group?

The Deputy Minister of Railways and Transport (Shri Alagesan): Yes, after a proper survey of the area has been carried out.

Shri Bhagwat Jha Azad: What would be the length of the road the construction of which, the hon. Minister has just now said, would be taken up by Government? Has any rough estimate been made by the the Ministry?

Shri Alagesan: I can only give a rough answer. It would be between 160 and 170 miles.

Shri Bhagwat Jha Azad: Would the Government tell us what are the transport facilities that are available at present in the three main islands in the Andaman Islands group?

Shri Alagesan t As I said before, before proceeding with this road, the islands have to be properly surveyed and the Survey of India has been carrying on the work, and we propose to construct portions of the trunk road. A rough alignment has been made which will be taken up during the second Five Year Plan.

Shri Bhagwat Jha Azad : As between the three groups of the island, there is much water. Therefore, do Government propose to devise an alternate system of transport, just like the present water transport system of 'moulis' for carrying on trade?

Shri Alagesan: As it is, the road may have to cross the sea in three places and perhaps we will have to take the road on it. I am not aware of the details of this matter.

Railway Workshop Reviewing Committee

*1921. Shri T. B. Vittal Rao: Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 559 on the 8th August, 1955 and state:

(a) whether any action has since been taken by the Railway. Board on 297 L.S.D.—2

the interim Report submitted by the Railway Workshops Reviewing Committee; and

19 SEPTEMBER 1955

(b) if so, the nature of the action taken thereon?

The Deputy Minister of Railways and Transport (Shri Alagesan) (a) and (b) Yes. This was a departmental committee and the report deals with departmental procedures and readjustments. Appropriate action where necessary has been and is being taken.

Shri T. B. Vittal Rao: May I know whether the final report has been submitted by this Committee, because, in reply to a question on the 8th August last, it was said that the Committee's report was expected by the end of August.

Shri Alagesan : Yes; It has been submitted.

Shri T. B. Vittal Rao: Could I know the main recommendations of this Committee?

Shri Alagesan: As it is, it is purely technical. Perhaps the hon. Member may understand it but I am not able to understand it. It runs to several pages. I do not think I should bother the House with that.

Shri T. B. Vittal Rao: May I know whether this Committee has found out that the capacity of some workshops has been under-utilised?

Shri Alagesan: I do not think I should go into every detail of the report of the Committee. It is a departmental Committee intended purely for action being taken by the department concerned. The Board has accepted many of the recommendations and is issuing instructions to the various railway administrations.

Shri Kamath: May I know whether a copy of the report will be placed on the Table of the House?

Mr. Speaker: It is a question of administrative detail. I do not propose to encourage that kind of probe into the administrative details. Unless there is some kind of principle involved, I do not think the question should come before the Parliament.

Shri T. B. Vittal Rso: The Railway Minister, in his speech during the budget session two years ago, said that this Committee was being appointed to go into the question of fully utilising the existing capacity in the railway workshops. That is why I want to know whether the Committee has found that some workshops are under-utilised.